भारतीय दवा नेटवर्क पर वीजा प्रतिबंध

अमेरिका ने 13 करीबी सहयोगियों के वीजा भी किए रद्द

वॉशिंगटन, 13 मई. अमेरिका ने भारत स्थित ऑनलाइन दवा विक्रेता केएस इंटरनेशनल ट्रेडर्स से जुड़े 13 करीबी व्यावसायिक सहयोगियों पर वीजा प्रतिबंधों की घोषणा की हैअमेरिका ने इस नेटवर्क पर देश में घातक और अवैध फेंटानिल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है.

विदेश विभाग के प्रवक्ता थॉमस टॉमी पिगॉट ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई उन अंतरराष्ट्रीय तस्करी अभियानों को ध्वस्त करने के एक आक्रामक अभियान का हिस्सा है, जो अमेरिका में परिवारों को तबाह करने वाली अवैध फेंटानिल के लिए जिम्मेदार हैं. विदेश विभाग के अनुसार, केएस इंटरनेशनल ट्रेडर्स ने कथित तौर पर पूरे अमेरिका में खरीदारों को अवैध फेंटानिल युक्त लाखों जाली दवाएं बेचींअधिकारियों ने कहा कि इस अभियान ने देश भर में अत्यधिक मात्रा में नशीली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों में योगदान दिया और कंपनी ने भारी मुनाफा कमाया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक कार्यकारी आदेश के तहत फेंटानिल को बड़े पैमाने पर विनाश का हथियार घोषित किए जाने के बाद, आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा के तहत ये वीजा प्रतिबंध लगाए गए थे. बयान में घोषणा की गई कि अमेरिकियों को जहर देने में शामिल लोगों को अमेरिका में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा.

> अमेरिकी अधिकारियों ने इस कदम को अंतरराष्ट्रीय दवा तस्करों और उनके वित्तीय नेटवर्कों के लिए एक चेतावनी बताया और इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और भारत फेंटानिल आपूर्ति श्रृंखलाओं को नष्ट करने और इस घातक दवा की बिक्री से लाभ कमाने वाले आपराधिक संगठनों को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का रिकॉर्ड मुनाफा

नई दिल्ली, 13 मई. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज करते हुए 1.98 लाख करोड़ रुपए का सर्वकालिक उच्च शुद्ध लाभ अर्जित किया है.यह लगातार चौथा वर्ष है, जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लाभ में रहे हैं.बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता, मजबूत ऋण वृद्धि और परिचालन दक्षता में सुधार ने बैंकों के प्रदर्शन को मजबूती दी है.

31 मार्च 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार 12.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 283.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया.इस दौरान कुल जमा राशि 10.6 प्रतिशत बढ़कर 156.3 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि सकल अग्रिम ऋण राशि 15.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 127 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई.

सोना और चांदी में आई तेजी

9000 रुपए महंगा हुआ सोना

18,000 रुपए उछली चांदी

नई दिल्ली, 13 मई. देश में सोना और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है, क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है. इस फैसले के बाद सर्राफा बाजार में सोना लगभग 9,000 रुपये और चांदी करीब 18,000 रुपये प्रति यूनिट महंगी हो गई है.

बढ़ी हुई लागत के चलते 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1.60 लाख रुपये और 1 किलो चांदी की कीमत लगभग 2.87 लाख रुपये तक पहुंच गई है. सरकारी फैसले के अनुसार अब सोने पर 10 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5 प्रतिशत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा, जिससे कुल प्रभावी टैक्स 15 प्रतिशत हो गया है.

यह कदम देश के चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

> पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ चुकी है. इस कारण कच्चे तदेल और गैस के आयात सरकार को ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है. सरकार दूसरे उत्पादों का आयात कम कर विदेशी मुद्रा की खपत कम करना चाह रही है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की.

चार दिन की गिरावट के बाद उबरा शेयर बाजार

49.74 अंक चढ़ा सेंसेक्स

121 अंक आगे रहा निफ्टी

मुंबई, 13 मई. विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार चार दिन की गिरावट से उबरने में कामयाब रहे और बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 49.74 अंक (0.07 प्रतिशत) चढ़कर 74,608.98 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक 121.70 अंक यानी 0.52 प्रतिशत ऊपर 23,501.25 अंक पर पहुंच गया.पिछले कारोबारी दिवस पर दोनों प्रमुख सूचकांक पांच सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुए थे. वृहत बाजार में ज्यादा तेजी रही.निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.22 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.64 प्रतिशत की बढ़त में रहा।ऑटो, आईटी, बैंकिंग, मीडिया और रियलिटी सेक्टरों में गिरावट रही.धातु शेयर का सूचकांक तीन प्रतिशत से अधिक चढ़ा.

एचपीसीएल का मुनाफा 77 प्रतिशत उछला

मुंबई, 13 मई. भारत की प्रमुख तेल विपणन और रिफाइनिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में मजबूत वित्तीय परिणाम जारी किए हैं. कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 77 प्रतिशत बढ़कर 6,065 करोड़ पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में बड़ा सुधार दर्शाता है.इस मजबूत प्रदर्शन के पीछे मुख्य कारण रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार रहा. कंपनी का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन इस तिमाही में बढ़कर 14.27 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 8.44 डॉलर प्रति बैरल था. बेहतर मार्जिन और ऑपरेशनल दक्षता ने कंपनी की लाभप्रदता को मजबूत किया.राजस्व के मोर्चे पर भी कंपनी ने स्थिर वृद्धि दर्ज की है.

अक्षय ऊर्जा उत्पादन में 20 प्रतिशत उछाल

ग्रीन एनर्जी में बड़ी छलांग, भारत में 95% नई क्षमता रिन्यूएबल

नयी दिल्ली, 13 मई.वित्त वर्ष 2025-26 में देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, जबकि कोयला और लिग्नाइट आधारित बिजली उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 4.3 प्रतिशत की गिरावट आयी है.

यह जानकारी काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर के ग्रीन फाइनेंस सेंटर के मार्केट हैंडबुक के नए वार्षिक संस्करण में दी गई है.हैंडबुक के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड स्तर पर 57.5 गीगावाट की शुद्ध बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ा है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 33.2 गीगावाट (एक गीगा वाट बराबर 1000 मेगावाट) की वृद्धि से काफी अधिक है.इस नयी बिजली उत्पादन क्षमता में लगभग 54.6 गीगावाट (लगभग 95 प्रतिशत) हिस्सेदारी अक्षय ऊर्जा (बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट समेत) की है.अक्षय ऊर्जा की बढ़ोतरी में 44.6 गीगावाट क्षमता के साथ सौर ऊर्जा (ग्रिड-स्केल और रूफटॉप) का योगदान सर्वाधिक रहा है.

इसके बाद पवन ऊर्जा में 6.1 गीगावाट की वृद्धि हुई है.भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता अब लगभग 533 गीगावाट पहुंच गई है, जिसमें अक्षय ऊर्जा (बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट समेत) का योगदान लगभग 52 प्रतिशत है. सीईईडब्ल्यू-जीएफसी की यह हैंडबुक भारत में बिजली और हरित प्रौद्योगिकी के वित्त पोषण और ऊर्जागत में बदलाव में उनकी भूमिका की निगरानी करती है.

> वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 30-30 साल की चार समान किश्तों में 6.98 प्रतिशत की कूपन दर पर 20,000 करोड़ रुपये के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए.वहीं, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तीन तिमाहियों में कुल 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया, जिसमें से 79 प्रतिशत निवेश अकेले सौर ऊर्जा क्षेत्र में गया.

एयर इंडिया ने कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कीं रद्द

मध्य पूर्व संकट और महंगे ईंधन का असर संचालन पर पड़ा.

तीन महीनों तक कम होंगी एयर इंडिया की विदेशी उड़ानें

नई दिल्ली, 13 मई. टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने बढ़ती जेट ईंधन कीमतों और मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच अपने अंतरराष्ट्रीय परिचालन में बड़ी कटौती करने का फैसला किया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, एयरलाइन जून की शुरुआत से अगले तीन महीनों तक कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित करेगी और कई प्रमुख रूट्स पर सेवाएं सीमित करेगी. दिल्ली से संचालित होने वाली जिन उड़ानों में कमी की गई है, उनमें शिकागो, नेवार्क, सिंगापुर और शंघाई जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गंतव्य शामिल हैं.इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को, पेरिस और टोरंटो के लिए भी उड़ानों की संख्या घटाई गई है.रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयर इंडिया ने कुल मिलाकर प्रतिदिन करीब 100 उड़ानों में कटौती की है. एयर इंडिया के सीईओ केंपबेल विलसन ने हाल ही में कर्मचारियों के साथ आयोजित टाउन हॉल बैठक में कहा था कि वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और लगातार बढ़ती ईंधन लागत के कारण एयरलाइन को परिचालन खर्च कम करने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं. एयरलाइन इस समय गंभीर वित्तीय दबाव का सामना कर रही है.

> पिछले तीन वर्षों में एयर इंडिया ने नीतिगत उल्लंघन और नैतिक कदाचार के मामलों में 1,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से हटाया है. सीईओ कैंपबेल विल्सन के मुताबिक, जिन मामलों में कार्रवाई की गई, उनमें एम्प्लॉई लीजर ट्रैवल सिस्टम का दुरुपयोग, विमान से सामान की तस्करी और अतिरिक्त सामान ले जाने की अनियमित अनुमति जैसे गंभीर उल्लंघन शामिल थे.

जीवीके एनर्जी के अधिग्रहण की योजना मंजूर

नई दिल्ली, 13 मई. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने जीवीके एनर्जी के अधिग्रहण की अडानी पावर की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है. आयोग ने मंगलवार को बताया कि उसने दिवाला कानून के तहत शुरू की गयी कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया के तहत जीवीके एनर्जी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है.

अडानी पावर उसकी शत-प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी. अडानी समूह की कंपनी के पास गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु में ताप ऊर्जा संयंत्रों का संचालन है.साथ ही गुजरात में उसका 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी है.

वहीं, जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की सहयोगी कंपनी जीवीके एनर्जी अपनी सहयोगी कंपनी एएचपीएल के माध्यम से उत्तराखंड के श्रीनगर में 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना में बिजली पैदा करती है.जीवीके एनर्जी एएचपीएल को संचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करती है. सीसीआई ने इसके अलावा किम्बर्ली क्लार्क कॉर्पोरेशन द्वारा केन्वू इंक के अधिग्रहण को भी स्वीकृति दी है.किम्बर्ली समूह भारत में मुख्यत: बच्चों के डायपर और महिला स्वच्छता से संबंधित उत्पाद बनाता है.केन्वू समूह दांतों तथा त्वचा के देखभाल से संबंधित उत्पाद और सौंदर्य उत्पाद बनाता है.

टाटा अल्ट्रोज आईसीएनजी अब ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ

मुंबई, 13 मई. देश की अग्रणी वाहन कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने बुधवार को अपनी प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज आईसीएनजी को ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (एएमटी) की शुरुआत की घोषणा की.

कंपनी ने बताया कि नयी अल्ट्रोज आईसीएनजी एएमटी की शुरुआती कीमत 8.69 लाख रुपये रखी गयी है.यह ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प के साथ देश की पहली और एकमात्र सीएनजी प्रीमियम हैचबैक है.

इक्सिगो ने लॉन्च किया एआई ट्रैवल ऐप 'तारा' का नया वर्जन

नई दिल्ली, 13 मई. ऑनलाइन ट्रैवल समाधान प्लेटफॉर्म इक्सिगो ने बुधवार को अपने एआई आधारित ऐप तारा का नया संस्करण जारी किया जो यात्रा की प्लानिंग से लेकर यात्रा के अंत तक के लिए विभिन्न प्रकार के समाधान पेश करेगा.

इक्सिगो के सह-संस्थापक रजनीश कुमार ने बताया कि तारा ऐप में एजेंटिक आई को जोड़ा गया है, लेकिन ऐप कै सभी पुराने फीचर और बटन पहले की तरह रखे गये हैं.यूजर संवाद आधारित बुकिंग कर सकते हैं.इससे यात्रा की योजना बनाना और बुकिंग करना अधिक आसान, स्मार्ट और व्यक्तिगत बन गया है.यूजर की पिछली बुकिंग और उसकी आदतों के आधार पर तारा अब उन्हें यात्रा की प्लानिंग के लिए सलाह भी देती है.उन्होंने बताया कि जब तक यूजर बुकिंग नहीं करा लेता उसे फ्लाइट के किराये में गिरावट के नोटिफिकेशन मिलते हैं.बुकिंग के बाद यह ऐप चेक इन खुलते ही खुद ही चेक-इन कर देता है.

समाचार विशेष

भाजपा के मजबूत क्षत्रपों को कमान

दिल्ली छोड़ बिहार, बंगाल, असम में कोई चौंकाने वाला नहीं आया

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी अब दूसरी तरह से लोगों को चौंका रही है. वह मजबूत क्षत्रप नेताओं को राज्यों में कमान दे रही है. बिहार में सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया गया. असम में हिमंत बिस्वा सरमा ही फिर से सीएम बनेंगे यह लगभग तय है. असल में पहले भाजपा के बारे में यह धारणा बनी थी कि वह किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है.

कहा जाने लगा था कि भाजपा पर्ची से निकाल कर सीएम के नाम तय कर रही है. राजस्थान में भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाए जाने के बाद यह धारणा बनी थी. ओडिशा में भी भाजपा ने दिग्गज नेताओं को छोड़ कर मोहन चरण मांझी को बनाया और छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय को कमान सौंपी. उत्तर भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत तब हुई थी जब भाजपा मे हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया था.

भाजपा के बारे में बनी इस धारणा के कारण ही जब बिहार में उसका अपना सीएम बनाने की बारी आई तो ज्यादातर लोग कह रहे थे कि कोई चौंकाने वाला नाम होगा. भाजपा किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है. सम्राट चौधरी के नाम को सिर्फ इस आधार पर खारिज किया जा रहा था कि उनके नाम की बहुत चर्चा हो रही है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको नहीं बनाएंगे. लेकिन अंतत: उनके नाम पर मुहर लगी. कोई चौंकाने वाला नहीं आया. कोई पर्ची नहीं निकली.

> **रणनीति में बदलाव की वजह लोकसभा चुनाव 2024 में लगा झटका**
>
> असल में भाजपा आलाकमान की रणनीति में यह बदलाव 2024 के लोकसभा चुनाव में लगे झटके की वजह से हुआ है पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 63 सीटों का नुकसान हुआ था और वह अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी. तभी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एक दिल्ली के अपवाद को छोड़ दें तो भाजपा ने हर जगह ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, जिसका बनना तय माना जा रहा था. महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़नवीस स्वाभाविक पसंद थे तो उनको बनाया गया. हरियाणा में तो भाजपा ने चुनाव ही लड़ा था नायब सिंह सैनी के नाम पर. उनको चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था और उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था तो वे सीएम बने.

नितिन गडकरी क्यों दूर हो गए?

नई दिल्ली. यह लाख टके का सवाल है कि नितिन गडकरी क्या कर रहे हैं? उनके मंत्रालय को लेकर गाहे बगाहे खबरें आती हैं वह भी पहले की तरह नहीं. पहले तो केंद्र सरकार के सिर्फ एक मंत्री की चर्चा होती थी और वह मंत्री होते थे नितिन गडकरी. उनकी चौतरफा जय जयकार होती थी.

उनके बारे में कहा जाता था कि वे सबसे अच्छा काम कर रहे हैं. अब भी उनके मंत्रालय की एकाध खबरें आती हैं. कभी पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की तो कभी टोल वसूली के ज्यादा आधुनिक तरीके की. हालांकि इसे लेकर उनका मजाक ज्यादा बनता है. लोग टोल वसूली के लिए उन्हीं को जिम्मेदार बताते हैं. राजनीतिक मामलों में उनकी खबरें अब नहीं के बराबर होती हैं. लेकिन अभी दो राज्यों में मुख्यमंत्रियों की शपथ में यह बात और उजागर हो गई. बिहार में सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे. नितिन नबीन के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा उसमें शामिल हुए. लेकिन नितिन गडकरी नदारद रहे. इसी तरह शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ के समारोह में भी गडकरी नहीं पहुंचे.

61 सीटों पर भाजपा 3 चुनावों से नहीं जीती

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में उतर चुकी है. पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया और अब पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने लगी है.

इसके तहत बीजेपी ने बूथों और लाभार्थियों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मंथनों का दौर शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में पार्टी पहले उन 61 विधानसभा सीटों पर पहले फोकस करने जा रही है, जहां पार्टी को पिछले तीन विधानसभा चुनावों में कभी सफलता नहीं मिली. 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के लिए सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है. बीजेपी चुनावों को बहुत ही पेशेवर तरीके से लड़ने के लिए जानी जाती है. एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि शुरुआती चरण में पंकज चौधरी ने बीजेपी नेताओं से कहा है कि पहले उन 61 विधानसभा सीटों से शुरू करें, जहां पर पार्टी 2012, 2017 और 2022 से लगातार हार रही है. इसके लिए पहले उन सीटों से जुड़े चुनावी गणित से जुड़े तमाम तथ्य जुटाए जाएंगे और फिर पार्टी वहां किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार सकती है, उसका खाका तैयार किया जाएगा.

उपचुनावों में बीजेपी को कमजोर सीटों पर मिला जीत का स्वाद- जिन 61 सीटों को बीजेपी अपने लिए सबसे मुश्किल मानकर चल रही है, उनमें से 22 पूर्वांचल में हैं. ये 22 सीटें पूर्वी यूपी के आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और मिर्जापुर जिलों में हैं. बीजेपी के लिए मुश्किल ऐसी लगभग 13 सीटें पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में हैं.

बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को अभी से सक्रिय कर रही

बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी चुनावों से पहले बूथ कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने की कोशिशें शुरू कर चुके हैं. उन्होंने बूथ से जिला स्तर तक की नियमित बैठकों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है. हर महीने रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद बूथ स्तरीय कार्यकर्ता बैठकें करेंगे और नेतृत्व को इस बारे में अपडेट देते रहेंगे. बूथ कार्यकर्ता लाभार्थियों के घरों में भी जाएंगे और तसल्ली करेंगे कि सरकारी की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक ठीक से पहुंच रहा है या नहीं और इसमें उन्हें हर संभव मदद करेंगे.

विशेष | कांग्रेस में छिड़ी कलह, राहुल गांधी ने बताई अपनी पसंद

केरल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री?

तिरुवनंतपुरम. केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को बंपर जीत मिली है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगला मुख्यमंत्री चुनने को लेकर है.

पार्टी को शानदार बहुमत मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और पार्टी के अंदर खींचतान खुलकर सामने आ गई है. मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए अपने भरोसेमंद नेता और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को आगे कर रहे हैं. वेणुगोपाल अलाप्पुझा लोकसभा सीट से सांसद भी हैं और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है. अब अगले दो दिन तक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को केसी वेणुगोपाल को ष्टरूपद के लिए समर्थन देने के लिए मनाएगी.

राहुल गांधी की केसी वेणुगोपाल के साथ अलग मीटिंग- खबरों के अनुसार, दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर कांग्रेस नेताओं की बैठक से पहले, राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल के साथ अलग से मीटिंग की थी. उन्होंने बताया कि वेणुगोपाल के खिलाफ कथित तौर पर एक अन्य प्रभावशाली पार्टी नेता वीडी सतीशन की मदद से मजाक उड़ाने वाले पोस्?टर लगाए गए थे.

वेणुगोपाल के खिलाफ हैं सतीशन- खबरों के मुताबिक, जब सतीशन बैठक में पहुंचे तो राहुल गांधी ने उनसे अपने खिलाफ लगे आरोपों के बारे में पूछा और इस दौरान सतीशन ने स्वीकार है कि वे वेणुगोपाल के मुख्यमंत्री बनने के खिलाफ हैं. सतीशन का तर्क था कि कांग्रेस महासचिव होने की वजह से वेणुगोपाल विधायकों पर गुट बनाने के लिए दबाव डालते थे. सतीशन ने साफ कहा कि उन्होंने कभी भी अपने फायदे के लिए गुट नहीं बनाए और केरल में विपक्ष के नेता के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान सभी विधायकों को साथ लेकर चले.इस बैठक में सतीशन ने कांग्रेस नेतृत्व से कहा कि अगर पार्टी ने नेनमारा, कझाकूटम, वडकानचेरी, नेदुमंगड और चेरथला में वेणुगोपाल के पसंद वाले उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा होता तो वह और अधिक सीटें जीत सकती थी.

> **सीएम की रेस में वेणुगोपाल आगे**
>
> बता दें कि केसी वेणुगोपाल पहले से ही इस दौड़ में सबसे आगे दिख रहे थे. लेकिन, कांग्रेस को ये तय करना है कि वह वेणुगोपाल जैसे केंद्रीय नेता को चुने या फिर जमीनी स्तर पर समर्थन प्राप्त किसी स्थानीय नेता को मुख्यमंत्री बनाएं. सतीशन के साथ ही रमेश चेन्निथला भी सीएम की कुर्सी के एक अन्य दावेदार हैं, जिनका दक्षिणी राज्य में काफी प्रभाव है. सतीशन को मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस की सहयोगी आईयूएमएल का भी समर्थन प्राप्त है.